डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

DFC News

डीएफसी समाचार

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
WE BELIEVE IN SINCERITY, SPEED & SUCCESS

वर्ष 7, अंक 22 जनवरी-मार्च 2016

माननीय रेल मंत्री ने डीएफसी की प्रगति पर जताई खुशी तीन नए कोरीडोर का प्रस्ताव

माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने डीएफसी की प्रगति पर खुशी जताई है। लोक सभा में रेल बजट 2016–17 पेश करने के दौरान उन्होंने कहा, **"समर्पित माल गलियारा (Dedicated Freight Corridor) परियोजना, जो देश में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है, गति पकड़ रही है। इस सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यह वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले, सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों के लगभग सभी ठेके दिए जा चुके होंगे। मेरे द्वारा कार्यग्रहण करने के बाद, 24,000 करोड़ रुपये मूल्य के ठेके दिए गए हैं, जबकि पिछले 6 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपये मूल्य के ठेके दिए गए थे।"**

श्री सुरेश प्रभु ने आगे कहा, **"माल यातायात व्यवसाय के तीव्र विस्तार पर बल को देखते हुए, संवर्धित यातायात के लिए नए समर्पित माल गलियारों का निर्माण करना अनिवार्य है जिसके अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए परिणामी लाभ होंगे। निम्नलिखित फ्रेट कोरीडोरों यथा दिल्ली को चेन्नै से जोड़ते हुए उत्तर–दक्षिण, खड़गपुर से मुंबई को जोड़ते हुए पूर्व–पश्चिम और खड़गपुर से विजयवाड़ा को जोड़ते हुए पूर्व तट को शुरू करने का प्रस्ताव है।"**

(रेल बजट 2016–17 पेश करने के लिए संसद में प्रवेश करते हुए माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु)

तीन नए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

- उत्तर–दक्षिण कोरीडोर (दिल्ली–चेन्नै)
- पूर्व–पश्चिम कोरीडोर (खड़गपुर–मुंबई)
- पूर्व तट कोरीडोर (खड़गपुर–विजयवाड़ा)

ड्रोन तकनीक से परियोजना की निगरानी

अपने रेल बजट भाषण में माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा," अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रकियाओं के अनुसार, हम परियोजना प्रबंधन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों का सहारा लेंगे। हम सभी बड़ी परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की कहीं से भी समीक्षा करने के लिए नवीनतम ड्रोन और जियो स्पैटियल आधारित सैटेलाइट प्रोद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं। अगले वित्त वर्ष में, समर्पित माल यातायात गलियारे की प्रगति की निगरानी करने के लिए इसे चालू किया जाएगा।"

डीएफसी ट्रैक पर दौड़ी पहली व्यावसायिक माल गाड़ी 30 मार्च 2016 को दुर्गावती से सासाराम तक चली ट्रेन

डीएफसीसीआईएल ने दुर्गावती से सासाराम तक पहली व्यावसायिक माल गाड़ी चलाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 30 मार्च 2016 को 56 किलोमीटर लंबे दुर्गावती–सासाराम सेक्शन पर पहली बार किसी व्यावसायिक माल गाड़ी का संचालन किया गया। यह संचालन पूरी तरह सुरक्षित एवं सफल रहा। दुर्गावती–सासाराम पूर्वी डीएफसी के मुगलसराय–सोननगर सेक्शन के अंतर्गत आता है। इस सेक्शन पर ट्रैक और ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा किए जाने के बाद इंजन रोलिंग जून 2015 में ही की जा चुकी थी।

(डीएफसी ट्रैक पर दुर्गावती–सासाराम के बीच गुजरती पहली व्यावसायिक मालगाड़ी)

डीएफसीसीआईएल ने प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत प्रदान की स्किल डिवेलपमेंट ट्रेनिंग

जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रतिभागी

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत् शुरू की गई डीएफसीसीआईल की पहल **'प्रोजेक्ट सक्षम'** का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी में परियोजना से प्रभावित एवं बीपीएल लोगों को और अधिक सक्षम बनाने के लिए रोजगार परक स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई। प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत चार परियोजना कार्यालयों के 13 केंद्रों में कुल 1039 लोगों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी गई। इनमें से 509 लोग बीपीएल परिवारों से हैं। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद अब सभी केंद्रों में प्रशिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रकिया शुरू हो गई है। अब तक महाराष्ट्र से 34 और राजस्थान से 33 लोगों का प्लेसमेंट किया जा चुका है।

डीएफसीसीआईएल ने दिसंबर 2015 में भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत मुंबई और इलाहाबाद में चार–चार, जयपुर में तीन और टूंडला में दो प्रशिक्षण केंद्र शुरु किए गए थे। इन केंद्रों में डेटा एंट्री ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल, कूरियर डिलिवरी, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेल्स जैसे नौ व्यवसायों की ट्रेनिंग प्रदान की गई। ट्रेनिंग कार्यक्रमों का उद्देश्य परियोजना से प्रभावित लोगों को रोजगार के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित करना है।

डीएफसीसीआईएल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशाला का आयोजन

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में आए विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते प्रबंध निदेशक श्री आदेश शर्मा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 09.03.2016 को दिसंबर 2015 को समाप्त तिमाही अवधि की डीएफसीसीआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री आदेश शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक महोदय की सहमति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए ।

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन करना हमारी संवैधानिक बाध्यता के साथ–साथ कानूनी अनिवार्यता भी है।

2. प्रबंध निदेशक महोदय ने रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे उपक्रम में विशेष रूप से विश्व बैंक एवं JICA के साथ पत्राचार किया जाता है फिर भी हमारा यह प्रयास रहता है कि हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। उन्होंने माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर हम अधिक से अधिक अमल करेंगे तथा राजभाषा के प्रयोग–प्रसार की दिशा में सार्थक कदम उठाएंगे।

3. प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि पिछली बैठक के दौरान मैंने निर्देश दिए थे कि मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए। इस संबंध में मुझे ज्ञात हुआ है कि मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय (टूंडला) आगरा में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित हो गई है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही अन्य परियोजना कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

4. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि सैप में भी हिंदी की सुविधा को चालू करने के लिए प्रयास किए गए हैं। आशा है कि इस ओर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई कर कार्य को पूरा किया जाएगा।

5. प्रबंध निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारीगण हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास करें।

6. प्रबंध निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि डीएफसीसी न्यूज पत्र में पृष्ठों की संख्या बढ़ाई जाए तथा हिंदी की सामग्री के प्रकाशन को अधिक स्थान दिया जाए।

7. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैने पिछली बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रतिदिन कम से कम एक पत्र हिंदी में अवश्य लिखें। मुझे आशा है कि अधिकारीगण इसकी अनुपालन करने में सार्थक पहल करेंगे।

8. अधिकारीगण जब भी परियोजना कार्यालय का निरीक्षण करें उसमें हिंदी कार्य का भी निरीक्षण करें तथा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति राजभाषा विभाग को प्रेषित करें ताकि इसकी राजभाषा विभाग को जानकारी प्राप्त हो सके।

हिंदी कार्यशाला का आयोजनः दिनांक 01 फरवरी–2016 से 08 फरवरी–2016 तक कॉर्पोरेट कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए छः दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजित किया गया। कार्यशाला के दौरान निदेशक राजभाषा, रेलवे बोर्ड, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के उप निदेशक, उप महाप्रबंधक राजभाषा आदि अधिकारियों के महत्वपूर्ण व्याख्यानों से कॉर्पोरेट कार्यालय के 35 अधिकारी एवं कर्मचारी लाभान्वित हुए। कार्यशाला की समाप्ति पर एक हिंदी कार्यशाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक महोदय एवं रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों के कर कमलों से नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

> "तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है।"
>
> गौतम बुद्ध

वर्ष 2015–16 की प्रमुख उपलब्धियां

प्रापण (Procurement)

वर्ष 2015–16 में सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग ऐंड टेलीकम्युनिकेशन एवं अन्य कॉण्ट्रैक्ट अवार्ड करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई। इस दौरान कुल ₹ 24,102 करोड़ के कॉण्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, जबकि इससे पहले के 6 वर्षों में कुल ₹ 13,209 करोड़ के करार हुए थे। परिणामस्वरूप 2138 किमी (76%) के लिए सिविल कॉण्ट्रैक्ट, 1786 किमी (63%) के लिए इलेक्ट्रिकल कॉण्ट्रैक्ट और 1356 किमी (48%) के लिए सिग्नलिंग ऐंड टेलीकम्युनिकेशन के ठेकों को अंतिम रूप दिया गया।

पश्चिमी डीएफसी

- रेवाड़ी–मकरपुरा सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन कॉण्ट्रैक्ट– मई 2015 में
- वडोदरा–वैतरना सेक्शन (320 किमी) के लिए सिविल कॉण्ट्रैक्ट– मई 2015 में
- 22 स्टील ब्रिजों के निर्माण के लिए सिविल कॉण्ट्रैक्ट (पैकेज 15 ए, 15 बी एवं 15 सी)– जून 2015 में
- रेवाड़ी–मकरपुरा सेक्शन के लिए सिग्नल ऐंड टेलीकॉम कॉण्ट्रैक्ट (पैकेज एसटीपी–5)– जून 2015 में
- रेवाड़ी–मकरपुरा सेक्शन (963 किमी) के लिए सिग्नल ऐंड टेलीकॉम कॉण्ट्रैक्ट (एसटीपी– 5 ए, टीपीडब्ल्यूएस)– अगस्त 2015 में
- मकरपुरा–जेएनपीटी सेक्शन (430 किमी) के लिए इलेक्ट्रिकल कॉण्ट्रैक्ट (पैकेज – ईएमपी 16) – जनवरी 2016 में
- इकबालगढ़–वडोदरा सेक्शन (308 किमी) के लिए सिविल कॉण्ट्रैक्ट– फरवरी 2016 में

पूर्वी डीएफसी

- कानपुर–मुगलसराय सेक्शन (402 किमी) के लिए सिविल कॉण्ट्रैक्ट एवं पीएमसी– मार्च 2015 में
- पूर्वी डीएफसी–1 के लिए सिस्टम कॉण्ट्रैक्ट (पैकेज 104)– मार्च 2015 में
- पूर्वी डीएफसी की क्युमलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के लिए कॉण्ट्रैक्ट अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर – 14.05.2015 को
- पूर्वी डीएफसी–2 के QSAC के लिए कॉण्ट्रैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर 18.11.2015 को

वर्तमान में चल रहे कार्यों की प्रगति

- रेवाड़ी–इकबालगढ़ सेक्शन में सीटीपी– 1 एवं 2 कॉण्ट्रैक्ट के अंतर्गत चल रहे सिविल कार्यों में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 1138 करोड़ रुपये की रकम खर्च की गई। इस दौरान 196 किमी एच/2 लेवल तक का निर्माण एवं 200 किमी एच लेवल तक का निर्माण किया गया। पश्चिमी डीएफसी के अंतर्गत आने वाले भगेगा में एनटीसी मशीन द्वारा मैकनाइज्ड ट्रैक लेइंग का कार्य शुरू हुआ।
- भाऊपुर–खुर्जा सेक्शन पर सिविल कार्य की अच्छी प्रगति हो रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्रगति रु.750 करोड़ थी । इस दौरान एच/2 और एच स्तर तक 92 किमी. के कार्य को पूरा किया गया। पूर्वी डीएफसी में भदान, मैथा और दाउदखान में एनटीसी मशीन द्वारा मैकनाइज्ड ट्रैक लेइंग का कार्य शुरू हुआ।
- पूर्वी डीएफसी के अंतर्गत देहरी–ऑन–सोन एवं सोननगर के बीच 3060 मीटर लंबे सोन ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान इसके निर्माण पर ₹ 111 करोड़ खर्च किए गए, जो इस पुल निर्माण की कुल अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत है।
- दिनांक 31.03.2016 तक पूर्वी डीएफसी एवं पश्चिमी डीएफसी में कुल 204 किमी तक ट्रैक जोड़ने का काम पूरा किया गया।
- विभिन्न राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत के फलस्वरूप, वे रेल ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) की कुल लागत को 50 : 50 के अनुपात में साझा करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसकी वजह से रेल मंत्रालय को नौ राज्यों से 121 आर.ओ.बी. के लिए सहमति मिल गई है, जिससे लगभग ₹ 2400 करोड़ की बचत होगी।

भूमि – अधिग्रहण

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 881 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 ए अधिसूचना जारी की गई। इस प्रकार, अब तक सोननगर–डानकुनि के बीच 6 हेक्टेयर की भूमि को छोड़कर, संपूर्ण पूर्वी डीएफसी के लिए रेल संशोधन अधिनियम 2008 के सेक्शन 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जा चुकी है। पश्चिमी डीएफसी में भी सेक्शन 20 ए के अंतर्गत भी अधिसूचना जारी करने का कार्य पूरा किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 783 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 ई अधिसूचना जारी की गई। इस प्रकार, अब तक, सोननगर–डानकुनि सेक्शन को छोड़कर, पूर्वी डीएफसी की 4323 हेक्टेयर भूमि (96%) के लिए रेल संशोधन अधिनियम 2008 के सेक्शन 20 ई के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं पश्चिमी डीएफसी में सेक्शन 20 ई के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने का कार्य 5974 हेक्टेयर भूमि (99.6%) के लिए पूरा किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 571 हेक्टेयर भूमि के लिए रेल संशोधन अधिनयम 2008 के सेक्शन 20 एफ के अंतर्गत अवार्ड किया जा चुका है। इसी के साथ कुल 9924 हेक्टेयर भूमि (पश्चिमी डीएफसी में 6000 हेक्टेयर में से 5717 हेक्टेयर और पूर्वी डीएफसी में 5673 हेक्टेयर में से 4207 हेक्टेयर भूमि) के लिए सेक्शन 20 एफ के अंतर्गत अवार्ड किया जा चुका है।
- इसके लिए ₹ 7956 करोड़ (पश्चिमी डीएफसी में ₹ 5017 करोड़ और पूर्वी डीएफसी में ₹ 2939 करोड़) का मुआवजा जारी किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 तक (सोननगर–डानकुनि सेक्शन को छोड़कर) 89.8% भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि कुल मिलाकर भूमि अधिग्रहण का कार्य 85% से ज्यादा पूरा किया जा चुका है।
- माननीय रेल मंत्री एवं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण सिडको की भूमि दर ₹ 84 प्रति हेक्टेयर से घटाकर ₹ 42 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है, जिससे ₹ 588 करोड़ की बचत हुई।
- चालू वर्ष के दौरान ₹ 4300 करोड़ का वितरण किया गया है, जो कि ₹ 11.5 करोड़ प्रतिदिन है। यह सभी संबंधित पक्षों के बीच अच्छे समन्वय एवं आपसी सहयोग के कारण संभव हुआ है।
- राज्य सरकारों में मुख्य सचिव स्तर पर निरंतर अनुनय एवं बातचीत के कारण पूर्वी डीएफसी में कुल 81 किमी के 92 पैच का अधिग्रहण किया गया जबकि पश्चिमी डीएफसी में कुल 84 किमी के 32 पैच अधिग्रहित किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भूमि से संबंधित 1325 आर्बीट्रेशन और 413 कोर्ट मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रकार अब तक 4016 आर्बीट्रेशन मामलों और 742 कोर्ट मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

वित्त

- **पूंजीगत खर्चों में तिगुनी बढ़ोत्तरी : वर्ष 2014–15 में ₹ 2885 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 8500 करोड़ (लगभग) का पूंजीगत व्यय किया गया।**

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी (CCEA) द्वारा डीएफसी का ₹ 81,459 करोड़ का प्राक्कलन (Estimate) अनुमोदित किया गया।
- दिनांक 30.06.2015 को पूर्वी डीएफसी–3 के लिए विश्व बैंक द्वारा 650 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया।
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से ₹ 5644.69 करोड़ (103664 मिलियन येन) के ऋण अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए JICA और डीएफसीसीआईएल के बीच एमओडी पर, दिनांक 22.01.2016 को, डीईए (वित्त मंत्रालय) एवं रेल मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
- CRISIL (क्रिसिल) द्वारा डीएफसीसीआईएल को CCR AAA (कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए) दिए जाने की पुष्टि।
- मूडी की एक ईकाई ICRA द्वारा भी डीएफसीसीआईएल को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए आईसीआरए ट्रिपल ए रेटिंग प्रदान की गई।
- फिच समूह की एक कंपनी इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने डीएफसीसीआईएल को दीर्घावधि रेटिंग INDAAA जारी की है।

अन्य उपलब्धियां

- डीएफसीसीआईएल की प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल नीति को अंतिम रूप दिया गया और 26.02.2016 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।
- डीएफसीसीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय को 5 स्टार बीईई रेटिंग प्राप्त हुई।
- वर्ष 2015–16 के दौरान सिविल, इलेक्ट्रिकल, एस ऐंड टी एवं वित्त श्रेणियों में 30 सहायक प्रबंधकों एवं 118 कार्यकारियों (Executives) की नियुक्ति।
- वर्ष 2015–15 के दौरान अनेक मानव संसाधन नीतियां अनुमोदित की गईं। इनमें शामिल हैं– मृत्यु मामलों में वित्तीय सहायता, यूनिफॉर्म भत्ता, बच्चों की शिक्षा का भत्ता, समावेशन, ई–2 का नया वेतनमान, जी.एस.एल.आई., बहु–उद्देशीय भत्ता, कल्याण, चिकित्सा नियमों एवं परिवार की परिभाषा में संशोधन एवं परिवहन भत्ता में संशोधन।
- 2015–16 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसके अंतर्गत चार मुख्य परियोजना ईकाइयों के 13 प्रशिक्षण केंद्रों में 1039 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/बीपीएल परिवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए 57675 कार्य दिवसों तक कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill Development Training) दिए गए।

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन

- **पत्रकार सम्मेलन (Press Conference)** : वर्ष 2015–16 के दौरान दो प्रेस वार्ताओं (07.08.2015 एवं 16.02.2016) आयोजित किए गए, जिन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रमुखता से जगह दी।
- **ऑडियो–विडियो फिल्में** : इस दौरान डीएफसीसीआईएल ने दो कॉर्पोरेट लघु फिल्मों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त डीएफसी की पर्यावरणीय विशेषताओं को दर्शाती एक अन्य फिल्म का भी निर्माण किया गया, जिसे 2015 में पेरिस में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेन्स में प्रदर्शित किया गया।
- **प्रेस विज्ञप्तियां** : वर्ष 2015–16 के दौरान 25 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा में भी प्रेस विज्ञप्तियां राष्ट्रीय मीडिया को प्रेषित की गईं।
- **व्यक्तिगत साक्षात्कार** : डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक के साथ संवाददाताओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार भी आयोजित किए गए, जिन्हें बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एवं मेल टुडे जैसे शीर्ष अखबारों ने प्रमुखता से छापा।
- **टेलीविजन पर विशेष कवरेज** : दिनांक 22.02.2016 एवं 23.02.2016 को ज़ी मीडिया के ज़ी बिजनेस एवं अन्य चैनलों पर डीएफसी पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम को डीएफसीसीआईएल के यू–ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकता है। लिंक–**https://www.youtube.com/ watch?v=g3vJGrNyJXs**
- **सोशल मीडिया पर डीएफसीआईएल** : सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए एवं लोगों के साथ सीधा एवं दो–तरफा संवाद स्थापित करने के लिए डीएफसीसीआईएल ने वर्ष 2014–15 के दौरान सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। डीएफसीसीआईएल अपने आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल एवं यू–ट्यूब चौनल के माध्यम से कार्यों की प्रगति से संबंधित सूचनाएं, तस्वीरें एवं विडियो साझा कर रहा है।

फेसबुक पेज

यू.आर.एल.
www.facebook.com/dfccil.india

शुरू किया गया - 26.05.2015 को

कुल लाइक्स - 1200 +

कुल पोस्ट - 55 +

अपलोड की गईं तस्वीरें/विडियो- 120 +

ट्विटर हैंडल

यू.आर.एल.
www.twitter.com/dfccil_india

शुरू किया गया - 09.09.2016 को

कुल फॉलोआरो की संख्या - 700 +

कुल ट्वीट्स एवं रिप्लाई - 150 +

संलग्न की गईं तस्वीरें/ विडियो- 50 +

यू-ट्यूब-चैनल

शुरू किया गया - 03.12.2015 को

उपलोड किए गए विडियो की संख्या - 08

सब्सक्राइबर्स की संख्या- 70 +

कितनी बार विडियो देखे गए- 4000 +

Green Energy Initiatives of DFCCIL

Scarcity of oil due to declining trend of oil discovery and realization of Green House Gas (GHG) effect causing global warning & undesirable effects had lead to use of alternate fuel / energy source. Major consumer of fossil fuel is transport sector & is, therefore, the major source of Green House Gas emission. Reduction in CO2 gas emission is the need of the hour globally and DFCCIL is also marking in roads in the field by taking various measures.

Measures adopted for reduction in CO2 emission

With the Introduction of Dedicated Freight Corridor i.e. EDFC & WDFC; totaling to about 3300 km, traffic from road sector shall shift towards rail i.e. to DFC network & being on electric traction; substantial reduction in emission of CO2 gas shall be achieved. EU has progressed significantly in reducing the CO2 emission; rail with electric traction as the cleanest mode of transport is contributing a lot in this.To find out the potential of CO2 reduction with introduction of DFC, a GHG study was carried out by DFCCIL with the help of World Bank, the outcome of the study are as under:

a) No-DFC scenario emits:

- 2.5 times more carbon emissions than DFC scenario in Eastern Corridor
- 5 times more carbon emissions in Western Corridor (Fig. 1.0).

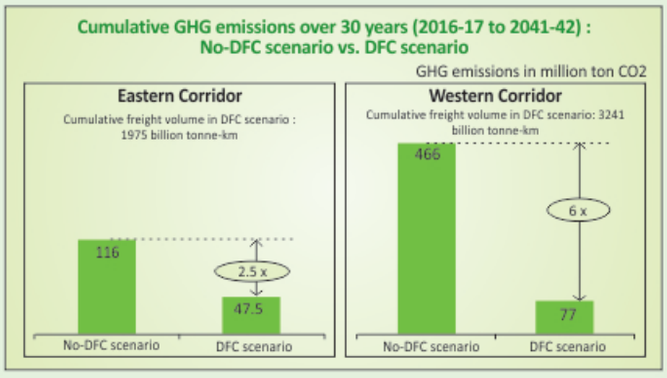

(Figure : Cumulative GHG emissions over 30 years (2016-17 to 2041-42): No-DFC scenario vs. DFC scenario)

a) Implementation of DFC ensures adequate capacity to carry freight –modal shift from road to rail- less GHG emissions.

b) Decrease in congestion.

c) Emissions due to construction of DFC and support infrastructure very low compared to operation related emissions

d) Coal and Container transport presently contribute major GHG emissions in the Eastern & Western Corridors respectively. Sensitivity analysis further confirms that No-DFC scenario is more carbon intensive than DFC scenario.

e) Technological interventions can further de-carbonize freight transport operations through the DFC.

Energy Optimization Study (EOS)

a) One of the major factor in train operation is energy efficient train driving. The way driver operates the train near curves, gradient, permanent & temporary speed restrictions and signal location; affects the energy consumption pattern of the train. On DFCCIL, the frequency of freight train movement shall be quite high and power density to the tune of 1 MVA/km is expected. For such a high traction power requirement; expected reduction in energy consumption by Driver Advisory system in the locomotive cab is going to be substantial. Keeping this aspect in mind, DFCCIL is carrying out "Energy Optimization Option Study" for entire DFC network with the help of World Bank.

b) This idea is to provide information about speeding, coasting and braking etc. to the driver, in locomotive cab by providing user friendly MMI. Based upon the advice displayed on MMI screen, driver shall take action to operate the train in particular advised mode. This step is going to save 8-10% energy and thereby reducing the carbon footprint significantly.

c) The study is in progress, Inception report is ready and final report and software & hardware models and specifications are expected to be ready by July 2016. The system is planned to be installed on all the locomotives that shall ply on DFC network. World Bank has another study for DFC in place for its implementation in the loco cabs. The contribution of this DAS to the nation's mission emission of reducing CO2 emission shall be a landmark step.

d) Energy Optimization Study for DFCCIL is useful in following ways

i. By advising train driver about energy efficient train operation through speeding & coasting locations.

ii. Instruction to train driver through "Energy Efficient Train Operation System".

iii. No change in loco-motive control circuit, additional screen shall be provided.

iv. Energy saving is possible through

v. Optimizing running speed.

vi. Control on auxiliaries of loco during long halts

vii. Lowering down of pantograph, after predetermined time period.

Solar Energy Initiatives for new installations:

As a green initiative, DFC shall be insulating solar power plants at various installations as the network, thereby reducing the CO2 emission. Total planned capacity on its network at present is 645.2 kWp. Besides, new DFCCIL Corporate office building coming up in NOIDA will be constructed as per New Energy Conservation Building Code-2015, which is being issued by BEE shortly.

(Bhupender Singh Bodh)
General Manger/Elect./Technical Services, DFCCIL

माह के उत्कृष्ट कर्मचारी

जनवरी 2016

श्री कुमार संभव चौधरी
सहायक प्रबंधक / इलेक्ट्रिकल
कॉर्पोरेट कार्यालय

श्री कुमार संभव चौधरी ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित इलेक्ट्रिकल एवं मकैनिकल पैकेज के पी क्यू दस्तावेज और बिड प्रपत्र तैयार करने एवं उन्हें अंतिम रूप देने की प्रकिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विशेष प्रयासों के फलस्वरूप टेंडर एवं प्राइस बिड की प्रकिया काफी कम समय पूरी कर ली गई।

मार्च 2016

श्री सतीश मनशारमानी संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करते हैं। कार्य के प्रति उनका दृष्टिकोण, साथी कर्मचारियों के साथ उनका मित्रवत् व्यवहार एवं कठिन परिस्थितयों में कार्य निष्पादन की उनकी योग्यता अनुकरणीय है। प्रशासन विभाग में अनेक अवसरों पर उन्होंने अपनी दक्षता को साबित किया है।

श्री सतीश मनशारमानी
प्रबंधक / प्रशासन /
कॉर्पोरेट कार्यालय

कार्य की प्रगति

पूर्वी डीएफसी के मुगलसराय–सोननगर सेक्शन में ड्रोन द्वारा परियोजना प्रबंधन एवं निगरानी

पश्चिमी डीएफसी के रेवाड़ी–इकबालगढ़ सेक्शन के अंतर्गत रेनवाल वायाडक्ट का निर्माण

पूर्वी डीएफसी के खुर्जा–कानपुर सेक्शन के अंतर्गत दाउदख़ान में वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ निरीक्षण करते प्रबंध निदेशक श्री आदेश शर्मा

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित। कृपया पत्र–व्यवहार इस पते पर करें: संपादक, डीएफसी समाचार,
चर्तुथ तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली– 110001, फैक्स 91-112345827, ईमेल: aloksharma@dfcc.co.in, rkhare@dfcc.co.in
वेबसाइट: www.dfccil.gov.in **संपादक:** आलोक शर्मा, **सह-संपादक:** राजेश खरे

www.facebook.com/dfccil.india **www.twitter.com/dfccil_india**